talists and ecologists regarding destruction of the Silent Valley forest, which is one of the only remaining tropical rain forests in the world, Government of Kerala has been requested to stop further work till the matter is discussed with the State

Increase in the price of coal

Government.

- 61. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the price of coal has increased more than double during the last year with the result that the common man has been badly affected; and
- (b) if so, the measures proposed to be taken by Government to bring down the price of coal in public interest?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) and (b). No, Sir. The cost of production of coal has not doubled during the last year. The average pithead price, reflecting the cost of production, as approved by Government has increased from Rs. 64.71 to 101.18 per tonne from 16th July, 1979. This increase is due to the increase in wages and cost of inputs.

With the increased coal production planned next year and adequate to transport arrangements, the price of coal to the consumer is expected to come down.

उपज योग्य मूमि तथा श्रश्चक के उत्पादन पर श्रपर ं सकारी जलाशय थोजना के प्रमास

- 62. श्री ग्रार० एल० पी० वर्मा, क्या कर्जा गौर सिवाई गौर कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या धपर सकारी जलामय योजना (ह्वारीकाग, बिहार) जिस पर कि लगभव

the term of the Man to amove the

46 करोड़ ६० की लागत आयेगी, के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 16,000 एकड़ उपज योग्य भूमि जलमंग्न हो जायेगी, 60 गांवों में रहने वाले लोग विस्थापित हो जायेंगे और अभ्रक की खानों में पानी भरने के कारण अभ्रक के उपादन में काफी कमी आ जायेगी।

- (ख) क्या इस योजना के पास के गिरिडीह ग्रीर उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में हजारी-बाग के जिलों के लोगों को किसी प्रकार के लाभ होने की ग्रपेक्षा हानि ही होने की ग्रामा है; ग्रीर
- (ग) यदि उपरोक्त भाग (क) ग्रौर (ख) के उत्तर हां में हों तो क्या सरकार का विचार इस व्यर्थ की योजना को समाप्त कर देने का है?

ऊर्जा, श्रौर सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) अपर सकारी परियोजना योजना आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट (1977-78) के अनुसार 16,000 एकड़ (6475 हैक्टेयर) बंजर तथा कृषि योग्य दोनों प्रकार की भूमि जलाशय के 172.9 मीटर के अधिकतम जलस्तर में जलमग्न हो जाएगी और 60 ग्राम प्रभावित होंगे। इस समय अभ्रक की किसी खान में काम नहीं हो रहा है और न ही इस क्षेत्र में किसी नयी खान के जलमग्न होने की संभावना है।

(ख) गिरिडींह जिले की इस स्कीम से कोई सिंचाई लाभ नहीं मिलेगा । छोटा नागपुर डिवीजन के हजारीबाग जिले में इस स्कीम से 4500 एकड़ क्षेत्र (1813 हैक्टेयर) की सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे ।

इस परियोजना में 77,226 एकड़ (29817 हैक्टेयर) भूमि की सिंचाई के अन्तर्गत लाने और 58,485 एकड़ (22581 हैक्टेयर) भूमि में सिंचाई को स्थायी करना परिकल्पित है ।

(ग) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Deletion of names from voters lists

- 63. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state.
- (a) how many names were cut out from the final printed list of voters in various constituencies during the last mid-term election to Lok Sabha;